Mr. Deputy-Speaker: I shall take it up later. Mr. Bhargava is not here. The hon. Minister said he is engaged in the other House. Therefore, I will take it up later.

Shri B. S. Murthy (Eluru): May I know, Sir, when it will be taken up?

Mr. Deputy-Speaker: As soon as this important work is over. Now, General Discussion will start regarding the PEPSU Budget.

Shrimati Sucheta Kripalani (New Delhi): Before you start, we would like to know when you are likely to take up Mr. Bhargava's motion.

Mr. Deputy-Speaker: At the end of the day.

Dr. S. P. Mookerjee (Calcutta South-East): May be tomorrow morning, after Question Hour.

Mr. Deputy-Speaker: I will say some time later.

P.E.P.S.U. BUDGET—GENERAL DISCUSSION

Mr. Deputy-Speaker: Now, the General Discussion will take place on the PEPSU Budget. Hon. Members are aware that fifteen minutes is the time allotted normally to every hon. Member except possibly the leaders of groups who may be given five minutes more if they want to intervene, or other spokesmen on behalf of their groups. I will allow first persons coming from PEPSU to speak.

Shri Bansal (Jhajjar-Rewari): I come from an area which is on the border of PEPSU, Sir. (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: I find this kind of difficulty arising every time so far as the Chair is concerned. I wish hon. Members also have the same experience. Those hon. Members who are intimately connected with a particular subject do not get up. They wait till opportunities are given to the others, and at the last moment they say that they come from PEPSU. What is it I can do in such circumstances? I am placed in a very embarrassing position from time to time, and therefore, unless hon. Members who come from that area and who are interested in the subject, start first, I will not give them opportunity later on, and there is no good quarrelling with me that I am calling others. Of course, every Member of Parliament is interested, but Members coming from PEPSU are naturally more interested. Therefore, hon. Members from PEPSU may start, and they need not wait till others have spoken. They will be given fifteen minutes each.

Shri Chinaria: And he can speak in English for the benefit of others.

Shri Bansal: On a point of order, Sir,

Hon. Members: No point of order.

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का कृतज्ञ हूं कि मुझे सब से पहले इस मौके पर अवसर दिया ।

पेप्सू बी० क्लास स्टेट है और उसका बजट आज डिस्कस किया जा रहा है । आंकड़ों से और हिसाब-किताब से तो मैं हमेशा घबराता रहा हूं लेकिन यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि पैसा है और लाखों आदमियों के खून पसीने की कमाई का पैसा है और उस की मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है । मेरे ऊपर उन लाखों आदमियों की जिम्मेदारी है जिनका पैसा खर्च हो रहा है । इसलिए इस के अन्दर पड़ने में घबराते हुए भी मुझे इस को स्टडी करना पड़ा और मुझे इस के लिये कुछ कहना भी है । लेकिन कुछ कहने से पहले में मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है वहां तक सब ठीक है और जब आंकड़े आ गये हैं तो पैसा भी वह देंगे ही । लेकिन कई बातें और हैं जिन की बाबत मुझे कहना है जो कि इस तमाम बात में रुकावटें होंगी ।

पैप्सू एक छोटी सी रियासत है जिस की ३५ लाख आबादी है और दस हजार मुरब्बा मील जिस का क्षेत्रफल है, ६४ लाख एकड़ जमीन है । खैर, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि यह ठीक है या गलत । आज तो बजट पर ही बातचीत करनी है । इस की आमदनी सन् १९५१–५२ में कोई साढ़े चार करोड़ के लगभग थी, यह एस्टीमेट था, लेकिन ऐक्चुअल आमदनी ६ करोड़ हो गई । सन् १९५२–५३ में पांच करोड़ का एस्टीमेट

था और आमदनी सवा ६ करोड़ तक हो गई, और इस साल ६ करोड़ ३४ लाख का अन्दाजा है और घाटे का बजट है। ६८ लाख का घाटा दिखाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले सालों को देखते हुए इस साल भी इतनी बढ़ोतरी हो जायगी कि घाटा नहीं रहेगा। खैर, अगर घाटा भी रहे तो मैं तो एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं जिस के आगे हमेशा घाटा चलता है। इसलिए मेरे बड़े घर पैप्सू में भी घाटा चले तो कोई परवाह नहीं। देखना तो यह है कि लोगों का काम ठीक से चलता है या नहीं। अब इस में भी मुझे तसल्ली है। जहां तक बजट का ताल्लुक है सोशल सरविसेज के लिए इस सात करोड़ में से १.७२ करोड़, यानी पौने दो करोड़ के करीब रखा गया है।

दूसरी तरफ़ एक और भी सन्तोष की बात है कि डैवलैपमैंट सरविसेज के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब बातों के लिए भी सवा दो करोड़ रुपये रखे गये हैं। लेकिन इस में एक चीज़ है कि जितनी रक़म इन दोनों पर मिल कर बनती है उतनी ही सिक्योरिटी सरविसेज और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लगा दी गई है। हम लोग यह उम्मीद करते थे कि आठ रियासतें मिली हैं तो उस से कोई न कोई सरविसेज म, एडमिनिस्ट्रेशन में बचत होगी। लेकिन बजाय बचत के वह सारे आदमी और सारा अमला इंटीग्रेट हो गया और उस के बाद भी कितने ही आदमी घुसेड़ दिये गये। आज बजाय इस के कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च कुछ कम होता, यूनियन बना देने से खर्च बढ़ा है। तो जहां एक तरफ़ सन्तोष है कि डैवलैपमैंट के लिये और दूसरी युटीलिटी सरविसेज के लिए काफ़ी रक़म रखी गई है वहां एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अधिक खर्च है कि उस में काफ़ी कमी की गुंजायश है।

आमदनी को देखते हुए एक बात खास तौर से दिखाई देती है। पैप्सू बजट में और पैप्सू स्टेट में ४० फी सदी हिस्सा आबकारी से आता है और ३० फी सदी शराब से आता है। जब कि हिन्दुस्तान में चारों तरफ़ आबकारी और शराब की कमी की गई, प्रोहीबीशन के ज़रिये और पाबन्दी लगा कर, तब उन्हीं दिनों पैप्सू के अन्दर शराब खुले आम बिकती है और उस ने अपनी आमदनी ८७ फी सदी शराब में बढ़ाई है। जब ऐसी हालत हो तो मैं नहीं समझता कि क्या हाल होगा। "जैसा खाये अन्न, वैसा हो जाय मन", तो जो शराब से पलेंगे वह कैसे अच्छा काम करेंगे। इसी तरह से पैप्सू में जहां एक तरफ़ से उस के घर पर अकाली साम्प्रदायिक विष की बेल छाई हुई हो और जिस को रजवाड़ाशाही का सहारा दिया गया हो और जिस की अफीम से और शराब से सिंचाई होती हो, वह बेल ज़हर नहीं उगलेगी, जहर का फल नहीं उस पर लगेगा तो इस से और ज़्यादा अच्छी क्या उम्मीद की जा सकती है। "बोये पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाय", यह चीज़ पैप्सू पर बिल्कुल ठीक साबित होती है।

एक माननीय सदस्य : महाराजा फरीदकोट।

श्री चिनारिया : हां, महाराजा फ़रीदकोट भी बहुत अच्छे हैं, जैसे पहले होते थे महाराजा पटियाला वैसे ही वे भी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। उसी थैली के महाराजा फरीदकोट भी हैं। अगर महाराजा पटियाला से भी हम लड़ते रहे हैं तो महाराजा फरीदकोट से भी लड़ते रहेंगे। और हमें तो अफसोस होता है कि राजप्रमुख को इस के बीच में क्यों लाया जाता है। मैं नहीं कहना चाहता। अभी आप ने यह मामला छेड़ दिया तो मैं आप से कहूं कि हम किसी भी राजप्रमुख के खिलाफ़ नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से उन के खिलाफ़ नहीं हैं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे नेताओं पर मैं खुदगरजी का इल्जाम लगा दूं तो वह बेजा नहीं होगा,

[श्री चिनारिया]

क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को हिन्दुस्तान से निकाल दिया, इम्पीरियलिज्म को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया, तब जा कर चैन लिया। लेकिन हमारे यहां जो फ्यूडल सिस्टम था, उस को हम अपनी स्टेट्स में कैसे बरदाश्त करें।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : वह भी निकाले जावेंगे।

श्री चिनारिया : इसलिए हर 'बी' पार्ट स्टेट के आदमी के दिल में जरूर यह विचार होता है कि जब तक उन के यहां से, पार्ट 'बी' स्टेट्स से रजवाड़ाशाही खत्म नहीं होती, जब तक उन के यहां से वह फ्यूडल सिस्टम खत्म नहीं होता जिस तरह से कि इस मुल्क से इम्पीरियलिज्म खत्म हुआ, तब तक आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करिये, कितना ही अच्छा बजट बनाइये, हालत ठीक नहीं होगी, नहीं होगी और बिल्कुल नहीं होगी। यह ख्याल सिर्फ मेरा ही नहीं है बल्कि 'बी' क्लास स्टेट के हर एक बच्चे बच्चे का है। कोई उस को उगल देता है और कोई चुपका बैठा है। लेकिन हर एक के दिल के अन्दर यही ख्याल है और दिल में जो चीज जोर करती है उस का असर होता ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बहरहाल आप को यह मानना ही पड़ेगा।

बजट के अच्छा होते हुए और रुपया बहुत लगाते हुए भी हमें कई शंकायें हैं कि यह ठीक जगह रुपया पहुंचेगा या नहीं और ठीक से काम होगा या नहीं। अव्वल तो इस को इम्प्लीमेंट करने वाली सरविसेज हैं। सरविसेज के अन्दर कई एक खामियां हैं जो कि रुपया लगाने में बाधा डालती हैं और पया लगाने में पूरा फायदा भी नहीं पहुंचने देतीं। अव्वल तो वहां सरविसेज के अन्दर करप्शन है। शायद वह सारे हिन्दुस्तान में होगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपने घर की देखनी है और मैं समझता हूं कि शायद नजदीक से ज्यादा दिखाई देती हो, लेकिन जितना करप्शन पैप्सू के अन्दर है, उतना शायद और किसी स्टेट में न हो। हालत यहां तक है कि काग़ज़ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर ले जाने के लिये पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क तक और दूसरे क्लर्क से तीसरे क्लर्क तक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। हालत यहां तक है कि काग़ज़ जाने ही नहीं पाता और ऐसी नजीरें मौजूद हैं कि पैसा आप नहीं देते तो काग़ज़ आपके सामने ही फाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो जहां यह हालत हो वहां काम कैसे हो सकता है। खाली रुपया खर्च कर के ही आसमान में नहीं पहुंच जाते। इसलिये आप को पहले सरविसेज को ठीक करना होगा।

दूसरी बात यह है कि सरविसेज म इनऐफीशियेंसी है। उन को मुल्क का इतना ख्याल नहीं है जितना कि तनख्वाह का ख्याल है और तनख्वाह से भी ज्यादा ख्याल रिश्वत का है। फिर वह कैसे काम कर सकते हैं और ऐफीशियेंट रह सकते हैं। एक बात और भी है। साम्प्रदायिकता वैसे तो सरविसेज में सब जगह है, चाहे वह हिन्दू साम्प्रदायिकता हो या किसी शक्ल की हो, लेकिन पैप्सू के अन्दर साम्प्रदायिकता सब से ज्यादा है। और रजवाड़ेशाही ने अपने को क़ायम रखने के लिए उस को और बढ़ावा दिया और अपने आदमी उन्होंने रखे, अपने लड़के रखे, अपने बच्चे रखे। और इस में हालत यहां तक है कि वहां साम्प्रदायिकता ही नहीं है बल्कि टैरीटोरियलिज्म भी है। आठ रियासतें थीं, सब से बड़ी उन में पटियाला थी। जब इंटीग्रेशन होने लगा तो पटियाला को सब से अच्छा दरजा दि-ा

गया। हर एक जगह पटियाला के आदमी को प्रिफर किया गया। इस में मैं यह नहीं कहता कि सिक्ख को प्रिफ़र किया बल्कि उस शख्स को प्रिफर किया जो कि उस फ्यूडल सिस्टम को ज्यादा ताकत पहुंचा सके। इसलिये तमाम की तमाम सरविसेज में ऐसे आदमी भरे पड़े हैं जिन में शुरू से आखिर तक साम्प्रदायिकता भरी हुई है।

● इसलिए मैं कहता हूं कि यह रुपया ठीक तरह से खर्च नहीं होगा। अभी मैं एक मिसाल देता हूं। लाखों रुपये एग्रीकल्चर के लिए सबसिडी के लिए दिये गये। आप उन के आंकड़े देखें कि किस जगह और किस किस को दिये गये। वह इलाक़ा जिस को हमेशा के लिए कोलोनी समझा गया, वहां एक पैसा भी नहीं दिया गया। उस को हिन्दी एरिया कहिये या हिन्दू एरिया कहिये। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में मैं पड़ूं। लेकिन आप फिगर्स देखिये कि सबसिडी के तरीक़े से और और भी जितनी तरह की चीजें हैं उन में से कितनी रक़म हिन्दी एरिया को दी गई और कितनी पंजाबी एरिया को दी गई। इसीलिए तो हिन्दी एरिया चाहता है कि पैप्सू से वह अलग हो जाय। इतना ही नहीं, म कितनी ही मिसालें और बता सकता हूं। एक कुएं के लिए पौने नौ सौ रुपये की सबसिडी दी जाती है। लेकिन मेरे इलाक़े में पानी बहुत गहरा है। एक कुएं के लिए वहां पांच हजार रुपये खर्च होते हैं। तो वहां तो यह सबसिडी दी नहीं जाती और जिस एरिया में नौ सौ या एक हजार रुपये में कुआं बन जाता है उस एरिया में यह पौने नौ सौ रुपये की सबसिडी दी जाती है। जहां क़हतसाली है, जहां पीने तक के लिए पानी नहीं, वहां यह सबसिडी नहीं दी जाती है। फिर इस सबसिडी की हालत क्या है कि २५ से ५० रुपये तक तो पटवारी को देने पड़ते हैं, कोई नक़शा वग़ैरह बनाने के लिए, फिर ग्रीकल्चर के सब इंस्पैक्टर के पास पहुंचन पर २५/५० रुपये देने पड़ते हैं। और शायद इंस्पैक्टर साहब १००/२०० रुपये मांगे। एग्रीकल्चर के डाइरैक्टर तो बड़े अफसर हैं, उन की नहीं कहता, मगर वहां तक पहुंचने में शायद ही कोई ऐसा हो कि जिस को तीन चार सौ रुपये तक न खर्च करने पड़ें और तब जा कर उसके चार सौ पांच सौ रुपये पल्ले पड़ते हैं। तो यह तो उस वाली बात हुई कि पहले जूती का इनाम मांगे और फिर उन में पांव दे। तो इसलिए हालत यह है कि जिन्होंने कुएं क़तई नहीं लगवाये वह सबसिडी लेते हैं, क्योंकि दो सौ तीन सौ वही दे सकते हैं जिन को कुछ खर्च नहीं करना है। वरना जिन को वाक़ई में खर्च करना है वह इतना खर्च कर के ६०० रुपये या पौने नौ सौ रुपये ले कर क्य करें।

इसी तरह से ट्रैक्टर के बारे में हालत है। पांच सात हजार की रक़म पाने के लिए वही खर्च कर सकता है जिस के पास इतना रुपया खर्च करने को हो। इसलिए यह उन को नहीं मिलता जिन को वाक़ई में ज़रूरत है बल्कि उन को मिलता है जिन के पास लाखों रुपये हैं और जो पहले ही काफ़ी रुपया लगा कर ट्रैक्टर वग़ैरह रखे हुए हैं। उन्हीं को यह ट्रैक्टर के लिये भी रुपया मिलता है। इसलिए महज़ पैसा देने से ही काम नहीं चल सकता, इसी से तरक्क़ी नहीं हो सकती। बल्कि पैसा कहां और कैसे खर्च होता है इस को देखने से असली तरक्क़ी होगी।

अभी पांच साला प्लान में भी भाखरा डाम पर ३५ करोड़ रुपया पैप्सू की तरफ़ से खर्च ही रहा है, लाखों एकड़ ज़मीन उस से सैराब होगी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस इलाक़े को पानी की ज़रूरत है, साठ फी सदी ज़मीन पर पानी नहीं आता है और हिन्दी एरिया के अन्दर महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर साठ फी सदी के बजाय ९९ फी सदी

[श्री चिनारिया]

में पानी नहीं आता है वहां भाखरा का पानी नहीं आयेगा।

वह पानी पटियाला से निकलता हुआ जाखल, सरसा होते हुए हनुमानगढ़ तक तो पहुंच जायेगा लेकिन दादरी की तरफ़ नहीं आ सकता, जहां कि ८४ हज़ार एकड़ ज़मीन सर्वे हो चुकी है। वहां की ज़मीन निहायत ज़रखेज़ है और वह सोना उगले अगर उस जगह भाखरा का पानी पहुंच जाय। वहां तक पानी नहीं पहुंचता, इसलिए कि पटियाला में रहने वाले आदमियों को उस इलाक़े का ख्याल नहीं, वह महज़ उस को एक कोलोनी समझते हैं जैसे कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान को अपनी कोलोनी समझते थे, आज महेन्द्रगढ़ की हालत बिल्कुल उसी तरह है....

Mr. Deputy-Speaker: He has already taken five minutes more.

श्री चिनारिया : श्रीमान्, आप मुझे पांच मिनट का समय और देने की कृपा करें और इस पैप्सू के मामले में मुझे इधर की पार्टी का लीडर समझ लिया जाय और इस नाते कुछ और अतिरिक्त समय दिया जाय। पैप्सू के अलावा दूसरे मामलों में तो लीडर बनने वाले बहुत हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस पेप्सू के मामले में मुझे लीडर समझ लीजिए।

Mr. Deputy-Speaker: No, no.

श्री अलग राय शास्त्री : पांच मिनट का समय दे दीजिए, ताकि यह अपनी बात खत्म कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए, लेकिन जल्दी खत्म कीजिए।

श्री चिनारिया : खैर, अभी और बहुत सी काम की बातें बतलाने को हैं और जब अब मुझे इजाजत मिल गयी है तो मैं थोड़ा-सा उन की बाबत ज़िक्र करूंगा। मैं आपको बतला रहा था कि भाखरा का पानी उस इलाक़े में जहां पानी की ज़रूरत थी, जहां क़तई पानी नहीं है, और ९९ परसेंट इलाक़ा रेनफैड है, उस जगह नहीं जाता, दूसरी जगह जाता है। मैं उस रास्ते को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आप को दूसरे रास्ते बतलाता हूं जिस से उस इलाक़े में जहां पानी की ज़रूरत है, आ सकता है, उस इलाके के अन्दर नरवाना ब्रांच का पानी जहां लगता है उस जगह भाखरा का पानी आ जायेगा। वह पानी बच कर आयेगा और इलाक़ा दादरी के लिये काम आ सकता है। दूसरे एक और भी चीज की जा सकती है कि जगाधरी और कर्नाल के वाटर लौग्ड एरिया में जो २२५ ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं, वही पानी इलाक़े दादरी में आकर इलाक़े दादरी और महेन्द्रगढ़ एरिया को जो डेफिसिट एरिया है सैराब और सेल्फ सफिशियेन्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर वह भी काफ़ी न रहे, तो मैं एक दूसरी चीज़ आपके सामने रखता हूं कि जगाधरी कर्नाल एरिया के साथ ही लगता हुआ सफ़ीदों पैप्सू का वाटर लौग्ड एरिया भी वैसा ही है जिस में पानी ऊपर आया हुआ है। उस जगह २५, ३० या ५० जितने भी ट्यूबवेल लगाये जायें और वह पानी नहर जमना में वेस्टर्न जमना में डाला जा सकता है, इतना पानी बढ़ा कर ८४ हज़ार एकड़ ज़मीन को पानी देना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रा ख्याल करने की ज़रूरत है। यहां पैप्सू के सेक्रेटरीज भी बैठे हुए हैं। उनकी मैं इस तरफ़ तवज्जह दिलाता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की मार्फ़त तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि उस इलाक़े का ख्याल करके आप वहां पानी दें।

इसके अलावा कम्युनिटी प्राजेक्ट्स का सवाल बहुत बड़ा है और इन की बाबत प्लानिंग मिनिस्टर ने हमेशा से यह पालिसी

फौलो की कि जो पालिसी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया फौलो करती आती थी कि जो पहले से अच्छा है उसको और अच्छा कर दो और मरते हुए को मरने दो। मेरे सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स सारे के सारे ऐसी जगह हैं जहां कि पानी खूब है, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी पैदावार बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन सच पूछिए तो जरूरत इन प्राजेक्ट्स की वहां है जहां पानी नहीं है। मरते तो वह लोग हैं, आपके पास अनाज ज्यादा भी हो जाये तो वह खरीदेंगे कहां से, क्योंकि उनके पास आमदनी के कोई साधन तो हैं नहीं। आप कम्युनिटी प्राजेक्ट्स ऐसी जगह करें जहां पानी नहीं है ताकि उन को पानी मयस्सर हो सके जिस से वह अपनी पैदावार कर सकें। उन जगहों पर हर तीसरे साल क़हत पड़ता है और वहां कोई लोगों के पास उद्योग धंधा करने को नहीं है। उनके लिए नई २ चीजों को करने के लिए कम्युनिटी प्राजेक्ट्स चाहिएं। यह तमाम के तमाम कम्युनिटी प्राजेक्ट्स उन जगहों पर करने चाहिएं जहां पर आबपाशी नहीं होती है और जहां क़हत ज्यादा पड़ते हैं और जहां खुश्क-साली रहती है। लेकिन होता इस के बिल्कुल बरअक्स है, एक भी जगह ऐसी नहीं जहां कि मुकम्मिल खुश्क इलाक़े में कोई कम्युनिटी प्राजेक्ट उन्होंने जारी किया हो। पिछले दिनों इंडियन कौंसिल आफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च में मैंने एक रेजोल्यूशन रक्खा था और उसको उन्होंने मेहरबानी फ़रमा कर युनैनीमस्ली पास भी कर दिया। लेकिन उस रेजोल्यूशन का इम्पलीमेंटेशन मैं अब तक होता नहीं देख रहा हूं। अब भी मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जारी करने हैं, वह मेहरबानी करके अकेले महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि जितने हिन्दुस्तान के खुश्क इलाके हैं, उन में इन को जारी किया जाय और उन के साथ प्रिफरेंशो किया जाये, तभी आपका मामला हल होगा, वरना यह कम्युनिस्ट भाई आपकी तमाम कमजोरियों को देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इन की निगाह इन की तरफ़ न पड़े क्योंकि नहीं तो उन के पंजे में वहां के रहने वाले फंस जायेंगे। अगर आपको अमनोअमान क़ायम करना है तो तमाम रुपया उस जगह लगाइये जहां लोग भूखे मरते हैं, जहां कमजोरी और दरिद्रता है।

इसके अलावा दो, एक छोटी २ बातें और हैं.....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री चिनारिया: दो मिनट मेहरबानी कर के मुझे और बोलने दें।

Mr. Deputy-Speaker: No, no; one minute more.

श्री चिनारिया: सिर्फ़ दो फ़िकरे कह कर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

Mr. Deputy-Speaker: All right.

श्री चिनारिया: मैं एक, दो इंडस्ट्रीज की तरफ़ कुछ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां एक डालमिया सीमेंट फैक्टरी और एक शुगर फैक्टरी हमारी थी, वह शुगर फैक्टरी यू० पी० में भेजी जा रही है।

दूसरी तरफ़ डालमिया सीमेंट फैक्टरी का ऐसा गलत इन्तजाम चल रहा है कि पहले जो मैनेजिंग एजेंसी थी, तेरह साल में पांच लाख रुपया मैनेजिंग एजेंसीज से आया, जब इस में नफ़ा नहीं रहा तो तेरह साल के लिए पांच लाख और सिर्फ पांच साल के लिए उन्हों ने ६ लाख ले लिया। २२ लाख रुपया आपने दूसरी फ़र्म्स को क़र्जे पर दे दिया, हांलाकि डिबेंचर्स, प्रिफरेंशयल शेयर्स हैं और जो जिम्मेदारियां हैं वह उस रुपये से अदा कर सकते थे। यही नहीं, अपनी मैनेजिंग एजेंसी पांच साल के लिए खत्म कर के ६ लाख रुपया ले लिया और डाइरेक्टर अपने ही रक्खे। मैं कहता हूं कि इस तरह सारी जगह जो आज

[श्री चिनारिया]

काम होता है, तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी आप नेशनलाइजेशन ला सकें, लायें, वरना कम से कम मैनेजिंग एजेंसी को तो खत्म कर दें ताकि यह लूट जो हम डालमिया सीमेंट फ़क्टरी में देख रहे हैं, उस लूट को रोका जा सके और इस के लिए मैनेजिंग एजेंसी को खत्म किया जाना चाहिए।

इस के अलावा हिन्दी के मुताल्लिक़ कुछ नहीं हो रहा है ....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order, please. I cannot allow the hon. Member to go on like this. Sardar Hukam Singh.

Sardar Hukam Singh (Kapurthala-Bhatinda): We have had just the pleasure of hearing our leader from PEPSU. I give him that credit. He has complained about certain things and discussed the Budget that was here for the first time. Certainly, it is a misfortune that this Union, that we have before us for discussion, previously consisted of some Sikh States. He has complained that there are Sikh servants there. But the circumstances have so happened that there were Sikh rulers and they could not be removed immediately. It was the covenant that all the officers and servants who were there previously should be retained; that was the promise. If he has that complaint, certainly, that has to be thrown overboard. Rather the pinch is on the other side. I express it. At any rate, since charge was taken over by the Adviser, many officers have been removed and not one Hindu has been removed. Not one servant appointed by the Congress Ministry when it was in charge was touched; but since this regime has come into power, they have singled out one after the other Sikh officers in responsible posts. In Education and other departments also, aged Sikh masters have been removed from charge and charge has been given to some non-Sikh lower qualified persons. Other instances are also there. I did not want to go into them, but this point has been touched upon by the previous Speaker, who claims to be a leader—and I acknowledge him to be so. My hon. friend also complained that the Hindi-Speaking areas had been neglected from the time PEPSU was formed. I would remind him that that was so most of the time the Congress remained in power and it was inspired by the Centre itself. But if he is complaining of the period 1952 when the Ministry was in power, he must remember that out of six Ministers, four Ministers came from Hindi speaking area. If he were to look into recruitment lists, he will find that a larger number of persons from that area were recruited in the services during that period, than persons from other areas. So his accusation is groundless and contrary to facts. The papers can be gone into very easily.

Then his complaint is that the Bhakra-Nangal project does not give his territory the water that he requires. That may be so. He says that his area was surveyed. Very good. If the surveys reveal that his areas are at a higher level, our engineers cannot make water go uphill. So that complaint should be directed against the engineers and, perhaps, against nature itself. So the complaint that water is not allowed to go into his fields is also without any real foundation.

Now I come to a review of the Budget that is now before us. This White Paper which gives a short survey of the things that have happened during the last year in PEPSU is dated 14th March, 1953. The Adviser went there on the 10th. Maybe he got it printed within those three days. But I presume that most of the things mentioned here, were perhaps formulated by the popular Ministry that was there. The survey that is incorporated in this White Paper presents nice and interesting reading. So far as the economic position is concerned, we find that this small and border State—as was observed by my hon. friend the previous speaker—has made remarkable progress. The White Paper says that the production of crops during 1952-53 has increased in all respects. In regard to food grains it is said that the figures compare favourably with an export of 37,000 tons. It is a surplus State and wheat to the tune of 59,000 tons was supplied to the neighbouring state of Delhi. In regard to prices it is said that prices were generally lower in 1952. It is said that cotton and sugar produced was much more this year than in the previous year, though there is some decline in prices that is expected to affect adversely the cotton production. Our Government should see to it and give proper care to see that this small tract does not suffer on that account.

The Patiala working class cost of living, the report says, has shown a steady downward trend. It is said that it has gone down by 30 points.

Though PEPSU is primarily an agricultural State, progress has been made in the field of industrialisation too. Then again it is said that the production of sugar was considerably higher in 1952 than in 1950-51. Production of cloth during 1952 was four times more than that of 1951. It will be seen from the above review that the year 1952-53 has witnessed a general improvement in the economic conditions in PEPSU. We are glad to find that this White Paper admits that during 1952, when the popular Ministry was in charge all round economic progress was achieved.

As I started by saying this is a border State. It has many problems. As was mentioned by the previous speaker, the Sikhs are in a majority and must be in a majority in the services too. We have to see whether we can recast the whole thing in the pattern of the other parts of India, whether we can rehash it and bring about changes slowly. It was said by about a new order or we should bring the hon. the Home Minister the other day in the course of the debates that democracy is new to India. Quite so. I agree with him there. There were no elections in the beginning and, therefore, there were no representative Legislatures. But it cannot be said that because there were no Legislatures, the States were badly run. I can say at least in regard to two or three States (Kapurthala and Faridkot) that the administration in them was much better than what it is today People admit it; masses know it. Even taking the Union of Patiala and East Punjab States, as a whole, as I have pointed out just now, remarkable progress has been made as could be done under the circumstances.

Then much has been said about the law and order position. Certain remarks made by my hon. friend Chinaria yesterday were not warranted at all. He referred to some abduction cases. He said that cattle were sold everywhere; but human beings were not sold. I may tell him that if he were to see and study the conditions in other States, perhaps he will not find things much better than what they are in PEPSU.

An Hon. Member: In which State?

Sardar Hukam Singh: I may tell my hon. friend of an incident which occurred in Agra. Agra has a population of more than three or four lakhs. My cousin's son was carried away from the second storey in the heart of the town and the dacoits wanted Rs. 40,000. My cousin took the Police Sub-Inspector with him. Rupees forty thousand worth of currency notes were signed by the Superintendent of Police and the Sub-Inspector delivered those notes to the dacoits. They have not been traced so far. We got our boy after paying them Rs. 40,000. That was what happened in the city of Agra. I approached Pantji and the Inspector-General of Police. Such instances can be cited in Saurashtra, Rajasthan, United Provinces and other places also. But if you are going to make one State the target of attack and carry on this propaganda, it is a different question. The newspapers might make it. But I say that all this is manoeuvred and engineered.

But you look to the circumstances. I do not mean to say that there has not been any improvement since the time the Adviser took over charge. It is but natural. If you make one man in charge of the State certainly there will be improvement. Dissolve this Parliament and this Ministry: give the administration over to Dr. Katju. Certainly a dictator will do much better. But would it be a better administration? Would you like it? Wherever a dictator is put in charge of any administration, there is bound to be improvement.

Shri Algu Rai Shastri: I would like to put you.

Sardar Hukam Singh: I know very well that I am not destined to be of that type.

If we were to compare the state of affairs as it was when the representative Government was in power, with what it is today when it is in the hands of one dictator, I admit—as I said at the very start—that there is some improvement: but not to the extent to which it is being propagated. I, therefore, refute and repudiate the improvement that has taken place in the position of law and order.

I have some figures with me which I quoted last time also. In February, 1952 there were 41 murders, in February, 1953 there were 21 Dacoities: they were ten in February, 1952; in February, 1953 they were five. Burglaries were 137 in February, 1952; there were 99 in February, 1953. Robberies: there were 35 during February, 1952; in February, 1953 there were only twelve.

An Hon: Member: Where does the hon. Member get these figures from?

Sardar Hukam Singh: From the records. Government can only repudiate or refute it by records. I have given figures. If it is any satisfaction to the hon. Member to know wherefrom I have got it, if he means I have stolen it he can proceed against me. But he

[Sardar Hukam Singh]

must listen to me and if they have no other figures, simply shouting "where-from have you got the figures?" will not do, that will not take their case any further. Simply asking where-from I have got them, is that an answer to my allegation and the figures I have placed before the House? Government is in possession of the figures. They have records. Let them come out if I am telling anything wrong. (*Interruption*). Now I must proceed, Sir, and I would request you to deduct the time of these interruptions.

Mr. Deputy-Speaker: There is no question of deducting. He himself chose to answer. He gave an illustration. It is open to some hon. Members now and then for the purpose of elucidation to put a question, not for interrupting. And it is open to the hon. Member on his legs who is in possession of the House to answer or not to answer. He may or may not give in. But if he chooses to give in I am not going to deduct that time. He answered and referred by way of illustration to Agra and so on. All that time cannot be deducted.

Sardar Hukam Singh: Would this be deducted, Sir?

Mr. Deputy-Speaker: Nothing will be deducted.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Let there be a flexible extension!

Sardar Hukam Singh: There is another thing. The time that the Adviser has taken over charge—he is a lucky man—is the harvesting season. The wheat is harvested, the *kharif* crop is not sown, the fields are open, and there is no hiding place. Therefore during these two or three months the incidence of crime is much lower than in other months. If credit is to be taken for that, I would advise the Government to compare it with the corresponding periods of other years and not gloat over the fact that crime has gone down in this period.

There is another additional reason. The Adviser must have been an honest man. He must have given instructions to the police stations that they should try to reduce these crimes as much as possible. But the police officials, out-Heroding Herod, whenever a case of dacoity comes they enter it as a case of robbery or theft and dacoity is not entered, because they feel that they will be able to give the impression that they have been able to reduce acts of dacoity. That also is a thing which I must ask Government to find out and enquire whether there has been an actual decline in crime or whether it is manoeuvred and engineered, I do not say by the Adviser himself but by others who want to show that they have done a great lot in this respect. We will be glad if it is really so. We will be prepared to give our co-operation to the Adviser. No man wants lawlessness. No man wants that there should be dacoities or robberies. I would be the first man to give him every help if he needs. If he can go on like that and reduce crimes, who would be happier than ourselves that he has done a good job? But that is not so. Let us not be complacent. The three gangs of robbers that were there are still at large. And I can cite recent instances where those dacoities have been committed, where those abductions have been committed, people have been carried away.

10 A.M.

And then an attempt has been made to represent it in a different manner. A charge was laid that the House that was dissolved only met for ten days.

The Minister of Finance (Shri C. D. Deshmukh): I am sorry to interrupt the hon. Member, but I would like to know the names of the dacoits that are at large.

Sardar Hukam Singh: I will give you that. But it is not now with me. I have got those papers but I cannot give you offhand.

Sir, you have said that you would not allow me extra time for these interruptions.

The Minister of Home Affairs and States (Dr. Katju): May I take it that my hon. friend is in contact with them?

Sardar Hukam Singh: Yes, just as the Home Minister was when he toured round there and people brought those applications. Certainly, and I have got some information from the Home Minister himself.

Shri Algu Rai Shastri: He simply wants notice!

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair.*]

Sardar Hukam Singh: It was said that the House was called to meet only for a few days and not a particle of legislation was done. Correct information was not given to the Home Minister. In this White Paper it is said and it is conceded that very useful and very necessary legislation was passed during the time that the Assembly met. There was also a reference yesterday that they passed three Bills and that they have been sent up to the Centre for assent. But the assent was not given. It was delayed and then there was some discussion with the Planning Commission

and others. Those very Bills were delayed here in the States Ministry and the charge was brought against that Ministry that they were not able to pass the legislation. They had passed it—it was admitted—and they had sent the same on for assent It was delayed here and now this charge is being brought against them.

Shri K. K. Basu: He has no correct information, it seems.

Sardar Hukam Singh: With regard to other legislation also, they were forwarded in the very initial stage, because that was a Part B State, and consultation was being held. They were to be taken up. But before that time the Assembly was dissolved. Therefore it was not fair to charge the Assembly or that representative Government that it was inefficient, that it could not go on with legislation or that it would not improve matters. This White Paper is a correct record to show that things are not just that way.

A very effective point was made the other day when the Proclamation was discussed that people used to cross over to the other side, that there was no honesty, that people could be won over, that Members could be won over. If it was a fact it was regrettable, it was unfortunate. But who were there, who were being sold and were ready for sale and who could be purchased? I beg to submit that they were only Congressmen. They were ready to cross over, ready for sale in the market. Every effort was made to win them over. The Maharaja of Faridkot with a fleet of forty cars remained there for fifteen days. It was known to the Congress bosses here. Every evening he was flying to Delhi in a plane and bringing other persons. Every temptation was offered to those Members that they might cross over and come to the Congress side. When that could not be effected, when no Member could be won over, the Maharaja of Faridkot wanted to distribute all his purse in the streets of Patiala. These things were known to every Congress leader here whom we worship and who knew it was being done. Then what was it that broke the camel's neck, the last straw? It was the crossing over of Takshak, the pillar stone of the Congress. When it was beyond all hope of repair and when the Congress found that there was no chance at all for it to be rehabilitated there, this course was adopted. I leave it there. That is a story which is painful.

I now come again to this White Paper and to the improvement that has been made. I say it is certainly commendable in a State like this which is very small in size, which is interspersed by some of the other States, Himachal Pradesh, Delhi, Punjab, Rajasthan at some places—parts of territories run into each other and therefore those effects, social economic and other, are felt there. And really it was that disease of Punjab from 1951 that infected PEPSU as well. With that precedent we are here confronted with that contingency, and I am afraid I should warn the adjacent States lest this disease spreads to Himachal Pradesh and other States as well. The people of these States might beware lest it overtakes them also. And I found that this small State was proceeding at a remarkable pace, at a wonderful speed and was making progress in every walk of life. The economic condition was much better and improvement had been made on all fronts when suddenly this blow of hammer came.

Again we have been told, and there is a very big propaganda in the Press, that the Adviser has done yeoman service and that he has made the preparation and revision of rolls two months earlier. That is a trickery, I should say. That is not fair to anybody or to the people of PEPSU. In the ordinary course, when the representatives of Government were there, every year, the rolls were prepared and revised and in 1952 they revised the rolls which were published in January, 1953. For the next year they are to be published in January, 1954. This January, 1954 is being utilised and exploited in this respect. The previous Government had the target that the rolls would be prepared and revised and published by January, 1954. To say that we have brought it earlier by two months I shudder to think what would be the fate of our country if this is the method that is adopted for such a propaganda.

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, कल से हम पैप्सू के मामलात पर बहस कर रहे हैं और पिछले दिनों वहां अमन और इन्तजाम में जो गड़बड़ रही मुख्तलिफ़ दोस्तों ने उस पर रोशनी डाली है। मैं ने कल अर्ज़ किया था कि मैं चूंकि इसी पैप्सू के एक हिस्से में रहता हूं, वहां के मामलात से मुझे बराहरास्त ताल्लुक है और हम वहां पिछले सालों में बहुत कुछ गड़बड़ देखते रहे हैं। आजादी के बाद जब यह यूनियन बनी इस यूनियन के बनने के बाद वहां के पहले प्रधान मंत्री ने यह बात कही कि

[डा० सत्यवादी]

इस यूनियन की शक्ल में हम ने सिक्ख होम बनाया है । और इस बात को उन्हों ने कई जगह दोहराया, जिसका मतलब था कि हम ने अपने देश के क़ानून की बिना जिस सैक्युलैरिज़्म पर रखी है वहां लोग उस के बरअक्स सोचते हैं और दूसरे रास्ते से चलना चाहते हैं । हम ने यहूदियों का वतन, मुसलमानों का वतन और ऐसी कई बातें सुनीं और देखी हैं । यहूदियों का जो वतन बना, उस ने मिडिल ईस्ट में जो गड़बड़ की, जो बेचैनी पैदा की, उस पर मुझे यहां बहस नहीं करनी है । मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जो इस देश को बांट कर एक टुकड़ा बनाया गया, वहां की हालत हम रोज़ देखते हैं । ऐसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तान का यह टुकड़ा इस क़िस्म का तसव्वुर पैदा कर के एक तबाही के रास्ते की तरफ़ जाना चाहता है । दरअस्ल बुनियादी ग़लती यह है कि पैप्सू में जब यह समझ लिया गया कि इस यूनियन की शक्ल में हम ने सिक्ख होम बनाया है तो इस से वहां रहने वालों के एक बहुत बड़े तबक़े के दिमाग़ों में बदगुमानी पैदा होने लगी और इस एक बुनियादी सबब ने इस की सियासत का ऐसा रुख़ कर दिया कि जो तबाही की तरफ़ ले जाता है । मुझे तो यह डर है कि सियासत के इस असर ने सिक्खिज़्म के रूहानी तसव्वुर को भी बहुत नुक़सान पहुंचाया है । जहां तक मैं ने मुताला किया है, स्वाध्याय किया है, मैं देखता हूं कि वह सिक्खिज़्म, जिस के दामन में बाबा फरीद, भक्त कबीर और भक्त रविदास जैसे महात्माओं के लिए जगह थी, आज यह उस सिक्खिज़्म को सियासत के दलदल में डाल कर उस के दमन को तंग करना चाहते हैं और आज इसी वजह से लोग उस को शुबहा की नज़र से देखने लगे हैं । इस पैप्सू को सिक्ख होम क़रार देने वाले दोस्तों से मैं यह कहूंगा कि वेसारे भारत को सिक्ख होम क्यों नहीं समझते । अगर हम उस के दूसरे पहलू को देखें तो क्यों नहीं उसी सिक्खिज़्म के सन्देश को, उस के पैग़ाम को ले कर वे भारत के कोने कोने में फैलाते । वे क्यों अपने आप को पैप्सू के इन चार ज़िलों की हदों में महदूद कर देना चाहते हैं । तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि आज उस इलाक़े में हर बात में इसी नज़र से देखा जा रहा है और हर मसले को इसी ढंग से हल करने की कोशिश की जा रही है जिस ने वहां के सारे के सारे निज़ाम को गड़बड़ कर दिया है । पिछले दिनों तो हम ने यह देखा कि यह गड़बड़, सियासत की कशमकश, इतनी गिरावट में चली गई कि वहां ताक़त हासिल करने के लिये लोगों ने डाकुओं का, राहज़नों का और ख़ूनियों का सहारा लेना शुरू कर दिया । हम तो यह सुनते रहे हैं कि वहां के लीडर, किसी जमाअत के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लीडरों के लिये यह कहा जा सकता है, कि वे इतनी गिरावट को पहुंच गये कि भटिंडा और दूसरे ज़िलों में जो कुछ हुआ वह आप सब को मालूम है । लेकिन वह जो कुछ हुआ वह डाकुओं का किया हुआ नहीं था । इन डाकुओं के पीछे जो सियासी डाकू बैठे हुए थे वे सब इस के लिये ज़िम्मेवार थे ।

तो, बहरहाल, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैप्सू की सियासत में इस बुनियादी ग़लती ने एक अजीब गड़बड़ पैदा कर दी और जितनी जल्दी हम वहां इन हालात को ठीक करें उतना ही हमारे सिक्ख भाइयों के लिये, हिन्दुओं के लिये और तमाम देश के लिये अच्छा और मुफ़ीद होगा । अब हम वहां प्रैसीडैंट का राज्य ले कर गये हैं । अमन और इन्तज़ाम के मामले में कल मैं ने अर्ज़ किया था और आज भी कहता हूं कि पिछले दो महीने के तजुर्बे से हमें यह महसूस हो रहा है

कि वहां हालात ने बड़ी तरक्की की है, इसलिये कि जिन लोगों के हाथ में अब वह इन्तजाम आया है वे तंग ख्यालात के असर से बाहर और आजाद हैं। तो मैं वहां की गड़बड़ के हालात की कुछ बातें आप को बताऊं जो कि वहां इस तरह से पैदा हुईं। एक पुरानी मसल मशहूर है कि "करेला और नीम चढ़ा"। कुछ तो रियासतों की पोल पहले ही मशहूर थी। पटियाले की बात मैं आप को बता रहा था कि वहां मुकद्दमात की कैफियत क्या थी। एक मुकद्दमे का जिक्र कल मैं कर रहा था कि २३ साल हो जाते हैं। जरा-सा जमीन का टुकड़ा जिसका मालिया कुल चार आने बनता है उस को २३ साल हो जाते हैं। उस अरसे में उस की नजूल की तहकीकात हो कर उस का फैसला नहीं हो पाता है और वह पटवारियों, कानूनगो और दूसरे ऐसे आदमियों का खिलौना बना हुआ है। इतनी उस जमीन की कीमत नहीं है जितना उस मुकदमे के सिलसिले में उस जमीन के ताल्लुक रखने वालों को खर्च कर देना पड़ा और उन को परेशानी उठानी पड़ी। मुकद्दमे की बात छोड़ कर मैं दूसरी तरफ जाता हूं। मैं ने आप से अर्ज किया कि मैं इसी पैप्सू के एक इलाके में रहता हूं। यह वह इलाका है जिस को कोहिस्तान का जिला कहते हैं। कोहिस्तान का इलाका यों कहिए कि हमारे देश में हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है। तो इस पैप्सू का यह वह जिला है जिस के मुताल्लिक यह आशा की जा सकती थी कि यह यूनियन बन जाने के बाद, देश के आजाद हो जाने के बाद, इस पिछड़े हुए इलाके की तरफ तवज्जह की जा सकेगी। लेकिन हम ने देखा कि पिछले चार पांच सालों के अन्दर वह हमारी तवक्कात पूरी नहीं हुई, हमारी वह आशाएं पूरी नहीं हुईं।

बजट पर सरसरी नजर डालने से मालूम होता है कि इन पहाड़ों में, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, जो रोज मर्राह की जरूरत हैं वह कम्युनिकेशन के जराए से पूरी होती हैं और इस की वहां बहुत ही ज्यादा कमी है। इस पर जितना धन वहां दिया जाता उतना ही यह इलाका तरक्की की तरफ जल्दी कदम उठाता। इस बजट में मेरा ख्याल है कि कंडाघाट, चायल, सड़क को पक्का करने के लिये रकम रखी गयी है और बाकी किसी सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस सड़क पर भी ध्यान दिया गया तो शायद इसलिये दिया गया कि चायल राजप्रमुख का गर्मियों में सैंटर होता है, पुराना समर सैंटर है। वहां पर उन्हें ही रोजाना जाना पड़ता है, उन बड़े आदमियों को जिनकी वहां पर कोठियां हैं। इसलिये वह सड़क जो पहले ही अच्छी हालत में थी, उस पर और रुपये खर्च करने का इन्तजाम किया जा रहा है।

एक दूसरी सड़क है जो शिमला से सुबाथू तक ब्रिडल रूट जाता है। उस का एक टुकड़ा सुबाथू से आगे जा कर मंडप से शुरू हो कर ममलीग तक जाता है। वह तो ऐसा रूट है कि वहां चला ही नहीं जाता। अगर इस सड़क को जो शिमले तक जाती है, मोटर के काबिल बना दिया जाय, तो बहुत सहूलियत वहां के तमाम के तमाम इलाके के लोगों को हो जाय। जतोग से लेकर ममलीग तक तो इतना टुकड़ा इस काबिल है कि उस को जारी कर के मोटर के काबिल बनाया जा सकता है। इस से सब से बड़ा फायदा होगा उन जमींदारों को जो अपने छोटे २ खेतों में सब्जियां पैदा करते हैं और शिमला ले जा कर बेच कर अपनी गुजर औकात करते हैं। वह लोग दो, दो मन सब्जी सिर पर रख कर पन्द्रह २ और सोलह २ मील ले कर जाते हैं। अगर उस रास्ते को मोटर के काबिल बना दिया जाय तो उस इलाके के आदमियों को बड़ा फायदा हो सकता है। सेहत के एतबार से

[डा० सत्यवादी]

और अस्पतालों के इन्तजाम के एतबार से देखिए तो सैरी एक छोटी-सी डिस्पेंसरी है। मुझे मालूम नहीं वहां अस्पताल में कोई डाक्टर आया भी है कि नहीं, लेकिन अभी दो साल के पहले की बात है कि वहां के इंचार्ज एक कम्पाउन्डर साहब होते थे। और वह कम्पाउन्डर साहब शराब के इतने आदि थे कि जब तक शराब की दो तीन बोतलें न पी लें, तब तक वह डिस्पेंसरी में नहीं आते थे। मुझे एक बार का वाक़या याद है कि मेरे एक दोस्त कम्पाउन्डर साहब को एक मरीज़ को देखने के लिए ले जाने आये, तो उन्होंने मुझ से फ़ीस पेशगी ले ली। पेशगी फ़ीस ले लेना कोई बुरी बात नहीं थी, चूंकि मरीज़ तक पहुंचने का रास्ता लम्बा था और सफ़र लम्बा था इसलिए उन्होंने पांच बोतलें शराब की अपने साथ रख लीं और कुन्हार तक पहुंचने में जो पांच-सात मील का रास्ता तय करना पड़ता है, उस दरमियान में चार, पांच बोतलें उडेल गये और कुन्हार पहुंचते-पहुंचते उन बेचारों की कैफ़ियत ऐसी बन गयी कि मुझे उनके लिए डाक्टर बुलाने की ज़रूरत पेश आई, मरीज़ को देखने को कौन कहे! तो मैं आप को बतलाना चाहता था कि वहां पर लोगों की सेहत का इन्तज़ाम बिल्कुल नाकाफ़ी है और उस के प्रति लापरवाही बर्ती गयी है। मेडिकल के बारे में सब से ज्यादा ज़रूरत तो मैं समझता हूं वह यह है कि वहां पर गर्भवती स्त्रियों के लिए मैटरनिटी सेंटर्स का प्रबन्ध होना चाहिए।

वहां पर सड़कें भी अच्छी दशा में नहीं हैं। सैरी से कंडाघाट तक का जो क़रीब १२, १३ मील का रास्ता है वह रास्ता इतना ख़राब है कि उस रास्ते मरीज़ नहीं जा सकते, कोई सड़क नहीं है जिस से उन को ले जाया जा सके। इस के अलावा एक दूसरा इलाक़ा है जो शिमले के कैथु इलाके से मिलता है और जिस को कैमिली परगना कहते हैं। वहां ठीक मेडिकल प्रबन्ध न होने के कारण बहुत सी गर्भवती स्त्रियां गर्भ की स्टेज में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर उन को वक्त पर मेडिकल इमदाद नहीं मिल पाती है। वहां ऐसे सेंटर नहीं हैं जिन में मरीज़ों को ले जाया जा सके, और पन्द्रह मील का यह रास्ता तय करने में ही उन का काम तमाम हो जाता है।

तालीम के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि वहां सैरी में एक प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल के लिए एक दुकान किराये पर ले रक्खी है। उस दुकान में बच्चे बैठे रहते हैं। वहां न कोई ठीक बैठने का इन्तज़ाम है और न ही फर्नीचर कोई ठीकठाक है। आप अन्दाजा कर सकते हैं कि इस पोज़ीशन में बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई कैसी होती होगी! उस इलाके में प्राइमरी स्कूलों की और आवश्यकता है। उस इलाक़े में एक हाई स्कूल भी है। ममलीग में एक मिडिल स्कूल है। मैं चाहता हूं कि आगे गहराई में जा कर शुकरा के क़रीब मिडिल स्कूल बनाया जाय तो वहां के बच्चों को आसानी हो जायगी। इसके अलावा टूटो में एक हाई स्कूल खोले जाने की ज़रूरत है तो इस से वहां के लोगों को बहुत आराम हो जायेगा।

सड़कों की बाबत मैं ने आप को बताया कि शिमला से सुबाथू वाली सड़क को मोटरेबुल किया जाये, इस के अलावा मंडप से ममलीग तक का रास्ता बहुत ख़राब है।

वक्त तंग है, अब मैं हरिजनों के बारे में कुछ कह कर बैठ जाता हूं। हरिजनों की दशा पैप्सू में बहुत ख़राब है और उन के साथ लापरवाही और सख़्तियां बर्ती गयी हैं और मालूम पड़ता है कि पिछले चुनावों के दौरान में हरिजनों ने जो रवैया वोट देने का अख़्तियार किया था, उस की उन्हें बड़ी सज़ा मिल रही

है । फ़िरकापरस्ती का वहां पर बोलबाला है । और आप को मैं एक किस्सा सुनाऊं जो कि एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है । तमाम भारत में महर्षि बाल्मीकि का जन्मदिवस असौज की पूर्णमासी को मनाया जाता है । लेकिन पैप्सू ने तमाम भारत में चल रही इस चीज़ को छोड़ कर अपने यहां कार्त्तिक की पूर्णिमा को महर्षि बाल्मीकि के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी कर दी है । अजीब तमाशा है । इस तरह की और भी कई बातें वहां पर हो रही हैं ।

पहाड़ी इलाकों में काफ़ी घास होती है जो काग़ज़ बनाने के लिए बाहर जाती है । उस इलाके में कालका के करीब कागज़ का कारखाना बनाया जा सकता है और जड़ी-बूटियों की रिसर्च के लिए सेंटर्स बनाये जा सकते हैं ।

इस के अलावा पहाड़ी इलाक़े में जितना स्टाफ़ पुलिस का बाहर से जाता है उन लोगों का रहन-सहन पहाड़ के रहन-सहन से बिल्कुल भिन्न होता है और खासकर पुलिस वालों का अखलाक़ भी जैसा होना चाहिए नहीं होता है । हमारे पहाड़ी इलाक़े में औरतें आज़ादी के साथ अकेली घूमती फिरती हैं और जंगलों से घास काट कर लाती हैं । तो जो पटवारी और पुलिस वाले इधर प्लेन्स से जाते हैं उन का अखलाक़ काबिले तारीफ़ नहीं होता इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहाड़ पर हम पुलिस और माल के महकमों में ऐसा स्टाफ़ रक्खें जिनका अखलाक़ दुरुस्त हो । टीचर्स स्टाफ़ में भी पहाड़ी स्टाफ़ रक्खा जाना चाहिए और हमें वहां पर ऐसा स्टाफ़ रखना चाहिए जो, जंगलों में घास लाती हुई और डंगर चराती हुई हमारी बहू बेटियां फिरती हैं, उन को अपनी ही मां बेटी समझें । बस में और अधिक न कह कर बजट प्रपोज़ल्स को सपोर्ट करता हूं ।

Shri Ranjit Singh (Sangrur): The Adviser an outsider, had been sent from Delhi with full powers to rule the State. The Adviser does not understand the language and customs of the people. All the political parties and all the officers of the PEPSU have been ignored and left out. Not a single man from PEPSU had been taken in the administration. The people of PEPSU think that the Central Government have treated them in a most unjust and unfair manner. On the 10th of March the Adviser took over charge and on the 12th of March he passed orders...

Mr. Chairman: Order, order. I do not want to interfere with the thread of the arguments of the hon. Member. I have found in all the speeches that have been made that they are of a general nature as if the Members were all speaking on the general situation before and after the assumption by the Central Government. I would request hon. Members who partake in the debate in future to kindly be specific in their criticism and at the same time see that their arguments relate to certain aspects of the Budget. A roving discussion like this will not be so beneficial.

Shri Ranjit Singh: The Adviser took charge on the 10th March.....

Dr. N. B. Khare: What is this? Locusts are coming in swarms.

Mr. Chairman: The House has to proceed with the business. I will request the hon. Members to see that no noise is made.

Shri Ranjit Singh: The Adviser took charge on the 10th. On the 12th, he passed orders that four officers should proceed on compulsory leave. He has made sweeping changes in the administration of PEPSU. Within the last seven weeks.....

Mr. Chairman: I am sorry to find that the noise is so great. I would request the hon. Members to hear the hon. Member who is speaking.

Some Hon. Members: He must also speak louder.

Shri Ranjit Singh: Within the last seven weeks he has taken action against 20 officers. With every change in the Government, if the officers are victimised, degraded and discharged, without any cause no Government in the State can be run on sound lines. The problem of PEPSU cannot be solved with such methods. By adopting such methods, the problems of PEPSU may become complicated. This is not the first time that action against officers has been taken. In 1949 when

[Shri Ranjit Singh]

the Malerkotla incident took place and the Sub-Inspector of Police was murdered in broad daylight in the *bazaar* of Malerkotla, four or five police officers were dismissed or suspended and the Inspector General of Police was asked to proceed on six months' leave. Later on these police officers were acquitted by the High Court and they had to be reinstated. The I.G. of Police, after six months, was compelled to retire. The people of PEPSU look to the Central Government which is the highest authority in the country today, for justice and fairplay. Let me tell you that the Adviser's rule in PEPSU will be judged by the people by his actions and deeds and not by his words, because actions and deeds are stronger and louder than words. The people of PEPSU are worse off than in 1946. The law and order position is not very satisfactory. People cannot travel from one place to another after sunset in certain areas. Highway robberies, bus hold-ups, dacoities and murders have been rampant in one part of the country or the other. Taxation during this period has gone high and people have to pay higher and more taxes than before. There is yet friction between the two major political parties and as long as this friction will continue and the agrarian trouble is not solved and PEPSU does not get a stable Government, I think there are no hopes for the administration of PEPSU to improve and if it improves, it will improve only for a certain period.

PEPSU is an agricultural State. More than 80 per cent. of the people live on land. The area is dry. The land is fertile and the people are hardy. If two crores of rupees are spent on tubewells, PEPSU can supply foodgrains worth Rs. two crores every year to the Government. The work on the Bhakra Dam and canal works that are already under construction, should be accelerated. These works, when completed, would bring prosperity to the State and great credit to the Government. In certain areas, the land revenues are higher than in others; these land revenues should be brought on par with the other areas. There are more than two lakh acres of land lying fallow and uncultivated. These lands should be reclaimed and tubewells should be constructed so that the lands could be irrigated. When these lands are reclaimed, they should be given to the landless labourers. This will increase food production and also the landless people will get land.

It is a matter of great relief that more than one crore of rupees have been provided for education in PEPSU. The people of the urban areas are getting all the facilities and amenities of life. There are schools, colleges, roads and hospitals. The people of the urban areas are often better off than the villagers. They can look after themselves in the matter of education. The villagers are very backward in education. They deserve help from the Government. Most of the money provided for education should be spent in opening more primary schools in the villages. About Rs. 35 lakhs have been provided for medical facilities. There are very few hospitals in the villages. More dispensaries should be opened in the villages and more touring dispensaries should be provided for the villagers, at least for two months during the malaria season. I would like to say one or two words about my friend Mr. Chinaria who said that in PEPSU there is a 'Kaka' rule. Well, I do not agree with my friend on this point, because, actually, PEPSU is ruled by the President. The Adviser is there to rule the State. These people—"Kaka" means young boys of tender age—belong to the State. They are born there. They are brought up there, and educated there. They are serving the State. And if proper enquiries are made about these boys, the Government will find that they are very honest—90 per cent. of them are very honest—and I think they are really an asset to the State, and I cannot understand what they should do and where they should go if they cannot live in their home.

The second thing is, he said certain things about lands, that lands were given by Maharajas to certain people. About lands, I would like to say that 30 or 40 years ago, there was not so much demand for lands. Lands were sold very cheap. About 30 or 35 years ago, at Lyalpur land was sold at Rs. 2,500 per square, and in Bikaner in 1924/25, lands were sold at Rs. 2,500 per square.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

During those days, lands in different parts of the country were given, at many places, free of charge to many people. So this charge of Mr. Chinaria will not stand. I may say that about 35 years ago the land prices were so low that it is not worth while putting this blame on the Maharajas.

I would request the Government that in PEPSU the Sikhs should be treated sympathetically, generously and liberally. I earnestly appeal to the Sikhs that their welfare, prosperity and good lies in acting in co-operation with the Government, and it is for the Government to win over the Sikhs by statesman-

ship, fairplay and justice. Therein lies the good of the country, the good of the Government and the good of the Sikhs.

LAW MINISTER'S SPEECH RE: SPEAKER'S CERTIFICATE ON INDIAN INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): Sir, under the Constitution, a Money Bill has been defined under clause.....

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): Before my friend goes on, may I make my position clear? I believe, Sir, you have received a communication from the Chairman of the Council of States, and he must have conveyed not only his own statement but also a copy of a Resolution which was unanimously adopted in the other House. By that Resolution, I am directed not to attend here either in my capacity as Law Minister or in my capacity as Leader of the Council in order to answer a charge which my friend Mr. Bhargava might choose to bring against me in respect of certain remarks reported to have been made by me in the other House the other day in connection with the Income-tax (Amendment) Bill. Therefore, if that is the matter which is going to be discussed, and if there is to be any charge brought against me, I cannot be here.

Shri Feroze Gandhi (Pratapgarh Distt.—West *cum* Rae Bareli Distt.—East): The Resolution passed in the Upper House may be read out.

Shri Syed Ahmed (Hoshangabad): Has the Resolution of the other House been received by you?

ملسٹر آف ایجوکیشن اینڈ نیچرل ریسورسز اینڈ سائنٹفک ریسرچ (مولانا آزاد): اصلی سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ تو یہ ہے کہ لا ملسٹر کا بیان اس بارے میں ہم سنیں۔

[The Minister of Education and Natural Resources and Scientific Research (Maulana Azad): The real question before us is to hear the statement of the Law Minister in this regard.]

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : लेकिन अपर हाउस में क्या हुआ है वह मालूम होना चाहिए ।

Shri Biswas: I may at once state here that in the statement which came from the Chairman of the Council of States you will find.....

Mr. Deputy-Speaker: I have not got the Resolution.

Shri Biswas: I do not know. The Resolution must have been sent Possibly, it will follow.

Mr. Deputy-Speaker: I shall read out the message I have received.

Shri Biswas: If you read out that message, that will make my position clear, because it was read out to me by the Chairman before he read it out to the Council, and I accepted that statement as quite correct.

Mr. Deputy-Speaker: I understand this is a copy that was given to the Secretary. Formally I have not received a copy, but anyhow, in view of the statement, I think this is correct. I shall, for the information of the House, read it out.

Shri Feroze Gandhi: On a point of order, Sir. When this communication has not been received by you, shall we take it as having been received by this House?

Several Hon. Members: No, no.

Mr. Deputy-Speaker: I understand that it was personally given by the Chairman to the Secretary.

Shri P. N. Rajabhoj: That is all right.

Mr. Deputy-Speaker: This is what I understand was read out in the other House by the Chairman. Now, when once a statement is made in the other House and a copy has come here, that is sufficient property so far as this House also is concerned. Let us see what exactly it says:

> "A mere complaint is not precluded and does not involve any breach of privilege of a member or of the Council. I am afraid that I cannot give my consent to this motion for privilege.
>
> There seems to be some misapprehension in regard to what happened in the Council on the 29th instant. Some members expressed a doubt whether the Bill in question was a Money Bill according to the requirements of article 110(1). A few felt that doubts could be raised even after the certificate was issued by the Speaker. At this stage the Leader of the Council referred to these doubts and suggested that it would reassure the House if it was told